सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

02 मार्च, 2017

षोडश विधान सभा   02 मार्च, 2017 ई0

पंचम सत्र   वृहस्पतिवार, तिथि   11 फाल्गुन, 1938(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः- सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः- महोदय, क्या हुआ ?

अध्यक्षः- नेता प्रतिपक्ष, आप पूछ रहे हैं क्या हुआ ?

श्री सत्यदेव रामः- अध्यक्ष महोदय, बिहार में बंगलादेशी मंत्री कौन है ?

अध्यक्षः- आप बैठिये न ।

श्री सत्यदेव रामः- महोदय, बंगलादेशी मंत्री कौन है, यह बिहार का अपमान है, इसका जवाब सरकार को देना होगा ?

अध्यक्षः- माननीय सदस्य सत्यदेव राम जी अभी आप बैठिये । यह कोई समय है अभी उठाने का, समय पर आप उठाईयेगा ।

श्री सत्यदेव रामः- महोदय, किसी को बंगलादेशी कहना राष्ट्रविरोधी है, इसपर सरकार को जवाब देना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः- आप इस तरीके से कर रहे हैं, यह गलत बात है ।

(इस अवसर पर माले के माननीय सदस्यगण कुछ बोलते हुए वेल में आकर बैठ गये)

माननीय सदस्यगण, आपलोग अपनी जगह पर जाइये । आपलोग इस तरीके से ....

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आपलोग सदन की कार्यवाही चलने देकर अपनी बात व्यवस्थित ढंग से क्यों नहीं कहना चाहते हैं ? यह हम नहीं समझ पाते हैं । सदन की कार्यवाही चलेगी तब न कोई आपकी सुनेगा ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य सत्यदेव बाबू, आप सदन को सुचारु रुप से चलाने के पक्षधर हैं और सुचारु रुप से सदन तब चलेगा, जब आप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइयेगा ।

(इस अवसर पर माले के माननीय सदस्यगण अपनी सीट पर गये)

अध्यक्षः- प्रश्नोत्तर काल ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल:- अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष:- नेता प्रतिपक्ष, सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही आपने हमसे पूछा कि क्या हुआ । क्या होना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको आमंत्रित किया था लेकिन आप कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी नहीं आये और हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ । हम तो चाह रहे थे कि आप कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में आइये । कल जो भी बातें हुई थीं, आपने देखा होगा, जिस मुद्दे को आपने उठाया, लगभग सदन के सारे सदस्य आपकी बात और आपकी चिंता से सहमत थे । एक मंत्री जी के द्वारा जो भी बातें कही गयीं या सभा में जो भी बातें हुईं, वह बिल्कुल ही अशोभनीय हैं और प्रजातांत्रिक प्रणाली में इस तरह की बात की कोई गुंजाईश ही नहीं है । आसन को इस बात से खुशी है कि लगभग सारे नेताओं ने, जिस दल से वे मंत्री आते हैं, उनके नेता, उनके अध्यक्ष, संयोग से दोनों ही इस सदन के सदस्य हैं, मंत्री भी हैं और जो मीडिया के माध्यम से हमने देखा है कि मुख्यमंत्री जी ने भी, आपने भी, कल आसन की तरफ से भी अशोभनीय कहा गया । हमने कहा था कि जो घटना अशोभनीय है, गलत है, उसको कोई सही नहीं कह सकता है । नेता प्रतिपक्ष और सदन के सारे सदस्य भी इस बात से मुत्तफीक होंगे या इत्तफाक रखेंगे कि अगर किसी एक ने अशोभनीय एवं निंदनीय आचरण कर दिया तो वह हम सब को अशोभनीय आचरण के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है । मगर हम उसकी निंदा तभी कर सकते हैं, जब हम अपने आचरण को संयमित रखें वरना हम भी उसी तरह का आचरण करें, हम भी सदन की मर्यादा के प्रतिकूल काम करें, हम भी सदन की प्रतिष्ठा को घटाने का काम करें और दूसरे को कहेंगे कि ये सदन की प्रतिष्ठा को घटा रहे हैं, राजनीतिक जीवन की प्रतिष्ठा को घटा रहे हैं, यह तो आपके लिए भी विचारणीय है । आपकी बात का समर्थन किया है, सारे दल के लोगों ने इसको गलत कहा है । आपके दल के माननीय अरुण बाबू आये थे और हमने इनसे अनुरोध किया है, इनसे आग्रह किया है कि आप दल के सभी नेताओं को हमारी ओर से अनुरोध पहुंचा दीजिये । आखिर यह सामान्य बात कल भी कहा था कि यह नैसर्गिक न्याय की भी मांग है और दूसरे अपने नियमावली में, जिस नियमावली को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, यह स्पष्ट प्रावधान है कि सदन के किसी सदस्य या वे मंत्री ही क्यों न हों, अगर उनपर कोई आरोप लगता है तो उसके संबंध में अपनी बात को सदन में रखने का उनका अधिकार बनता है । हमने कल भी कहा था और आज भी अरुण बाबू से कहा था कि वे अपनी बात को रखते हैं तो उनकी बात से सहमत होना या उनकी बातों को खारिज कर देना यह आपका निर्णय हो सकता है । हमको उस संबंध में कुछ नहीं कहना है लेकिन अगर कोई सदस्य या मंत्री जिसपर कोई आरोप लगा है, अगर वह अपनी बात कहना चाहता है, अपना स्पष्टीकरण देना चाहता है, उसको मानिये या न

मानिये, वह तो आप पर निर्भर करता है लेकिन उनको अपना स्पष्टीकरण देने का या अपनी बात कहने का मौका नहीं देना, मेरे ख्याल से यह अच्छी बात नहीं है । यह मैंने आपसे भी अनुरोध किया था, अरुण बाबू से भी अनुरोध किया है और हमें जो सूचना है, संबंधित माननीय सदस्य या माननीय मंत्री अपनी बात को कहना चाहते हैं, यह आसन का भी फर्ज है, अगर आप पर या किसी भी माननीय सदस्य पर कोई तोहमत आती है या आरोप आता है, कोई लांछना की बात होती है तो उस परिस्थिति में अगर वह अपनी बात को कहना चाहता है तो यह तो आसन का दायित्व है कि हम सदन से अनुरोध करेंगे कि उनको अपनी बात कहने का अवसर दिया जाय, मानना न मानना यह तो पूरे सदन पर निर्भर करेगा । चाहे वह सत्तापक्ष हो या विपक्ष हो, आप मानिये या न मानिये, उनकी बात को खारिज कीजिये । दूसरी बात मैंने अरुण बाबू से भी कहा है कि आसन का, आप विपक्ष हैं, सत्तापक्ष है, आपके अपने दायित्व हैं, फर्ज हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपना फर्ज निभाइये । सत्तापक्ष का अपना फर्ज होता है, वह अपनी बात कहे लेकिन आसन का फर्ज तो हर समय यही होगा, चाहे किसी तरीके से, अगर सदन की कार्यवाही चल सकती है तो चलावे । सदन न तो विपक्ष का है और न ही सत्ता पक्ष का है । आसन तो माननीय सदस्यों का है । सारे सदस्यों की चिंता या सारे सदस्यों का जो कंसर्न होगा, वही आसन का कंसर्न होता है ।

टर्न-2/सत्येन्द्र/2-3-17

अध्यक्ष (क्रमशः): हम सब जन प्रतिनिधि आये हैं, ठीक है अपनी बात कहकर प्रोटेस्ट करने का, प्रतिकार करने का तरीका आपका अपना हो सकता है लेकिन हम फिर से आपसे यही आग्रह करेंगे कि अगर आपने या जो सारे सदन ने एकमत होकर जिस सदस्य या मंत्री के आचरण को अशोभनीय कहा है, अगर वे अपनी बात सदन में रखना चाहते हैं तो उनको अवसर दिया जाना चाहिए नम्बर-1 और नम्बर- 2 मानना नहीं मानना सदन पर निर्भर करता है । आप सब की अगर किसी बात में एक राय हो जाती है तो फिर आसन की मजबूरी होती है कि वह उसी के साथ जाता है, उसमें आसन कोई अपना विवेक या अपना डिस्क्रीशन इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि आसन तो सदन के साथ चलता है । हमारा काम है आप सभी सदस्यों को देखते रहना, आप सभी सदस्य जो मिलकर कहते हैं, आसन कभी उससे अलग नहीं जाता है लेकिन अगर कोई अपनी बात कहता है तो सुन लीजिये । अगर उसको आप खारिज करते हैं तो आप अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपका तरीका है लेकिन उसमें भी मेरा एक सुझाव और करबद्ध प्रार्थना यही होगी । हमने नेताओं की बैठक में भी आपसे कहा था कि विरोध करने का, प्रोटेस्ट करने का भी जो एक संयमित तरीका होता है, नियमानुकूल व्यवस्था है उसके तहत करना ही उचित होता है, वरना एक अशोभनीय आचरण आप दूसरे अशोभनीय

आचरण से कर के प्रोटेस्ट करिये तो यह फिर चेन बन जायेगा और प्रतिक्रियाओं की एक लंबी श्रृखंला बन जायेगी । अगर वे आज कुछ बोल रहे हैं फिर उसके विरोध में कल आपकी तरफ से कोई इस तरह की अशोभनीय बात हो जायेगी फिर उसके रियेक्शन में दूसरी तरफ से अशोभनीय बात हो जायेगी । हमने आज तो बैठक इसीलिए बुलाई थी और संसदीय प्रणाली में एक से एक इससे भी दुरूह और कठिन संकटमय परिस्थितियों में इसी तरह की बैठकों में विचार करके हमलोगों ने उसका रास्ता निकाला है और इसीलिए हमने आपको आमंत्रित किया था । इसलिए अभी भी हम आग्रह करेंगे दो चीज के लिए कि अगर माननीय मंत्री या इस दल के सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनको मौका दिया जाय और अगर आप संतुष्ट नहीं है तो फिर कहिये । हमेशा आसन पूरे सदन की भावना से सहयोग करने के लिए तैयार है । हम अपने यहां आप सब लोग को, सरकार को, आपको फिर बुलाकर इसका क्या रास्ता निकल सकता है, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप आईए बात कर के हमलोग रास्ता निकालें।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अच्छी पहल की है । आपका अच्छा प्रयास हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आसन से यह जानना चाहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष सिर्फ अपनी बात कहेंगे या दूसरे की भी बात सुनेंगे । आज कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई महोदय, इतने बड़े इश्यू को ये उठा रहा हैं और कार्यमंत्रणा में इनको आने की फुर्सत नहीं है महोदय और इस तरह सदन में अपनी बातों को सिर्फ मनवाना चाहते हैं और दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनना चाहते हैं । मैं आसन से आग्रह करना चाहता हूँ, इनसे आग्रह करिये कि दूसरे पक्ष की भी बात सुनिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: प्रेम बाबू श्रवण बाबू ने इतना ही कहा है कि आप बोल लीजियेगा तो दूसरे लोग भी बोलें तो सुनियेगा ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल: महोदय, श्रवण बाबू माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी हैं उनको ज्यादा ज्ञान है इसका, उनको खड़ा नहीं होना चाहिए था जब आसन ने अनुमति मुझे दे दिया था महोदय आपने आदेश दिया, हम बैठ गये थे महोदय, हम कहना चाह रहे थे कि आपने अच्छा प्रयास किया, अच्छा पहल किया है, इसका हम बहुत स्वागत करते हैं ।

अध्यक्ष: हम आगे भी करेंगे।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल: और आगे भी करेंगे यही मुझे उम्मीद भी है । लेकिन महोदय, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक, सर्वदलीय बैठक बुलाते आप हैं, उसमें हमलोग हमेशा शामिल होते हैं और प्रयास रहता है सदन चले और जो आप फैसला लेते हैं, वह लागू होता है लेकिन महोदय हम देख रहे हैं कि कार्यमंत्रणा समिति में माननीय मुख्यमंत्री भी सदस्य हैं, सर्वदलीय बैठक में उनको भी आमंत्रित आप करते

हैं लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी को जब इतना बड़ा इश्यू है जिससे बिहार का सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, एक मंत्री के चलते महोदय तो उनको बैठक में आना चाहिए था । सदन में भी नहीं आ पाये है तो क्या कारण है महोदय हम जानना चाहते हैं कि कार्यमंत्रणा समिति में सर्वदलीय बैठकों में मुख्यमंत्री नहीं आते हैं, नेता प्रतिपक्ष का भाषण होता है तो एबसेंट हो जाते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, प्रतिपक्ष की बात को सुनना नहीं चाहते हैं तो हम चाहेंगे महोदय...

(व्यवधान)

महोदय, हम कहना चाहते हैं आप सुनिश्चित कीजिये । महोदय, आप सुनिश्चित कीजिये कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में, सर्वदलीय बैठक में नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री रहे, प्रेम कुमार आगे बढ़कर रहेगा महोदय लेकिन महोदय मुख्यमंत्री एबसेंट हो जाते हैं नेता प्रतिपक्ष का भाषण हुआ तो एबसेंट हो गये तो सरकार गंभीरता से इस मामले को नहीं ले रही है । राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है और हमलोगों का एक ही स्टैंड है महोदय, हम आग्रह कर रहे हैं नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री सदन में आये और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले और असंसदीय आचरण करने वाले मंत्री को नीतीश कुमार जी बर्खास्त करें । हम स्वागत करेंगे, हमारा ये मांग है और मुख्यमंत्री जी को बुलाईए । मुख्यमंत्री सदन में आये, अपनी बात को रखें, मुख्यमंत्री जी आये, हम स्वागत करेंगे, मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करें महोदय और मामला साबित हो गया है । अब सफाई की जरूरत नहीं है । आपसे एक ही आग्रह महोदय है कि माननीय मुख्यमंत्री सदन में आये और सदन की कार्यवाही चलाये यह निवेदन महोदय है।

अध्यक्षः हमको लगता है प्रेम बाबू कि शायद मुख्यमंत्री जी को यह आभास है कि आप भी सरकार में उनके साथ रहे हैं, आप भी मंत्री रहे हैं और उस समय भी जब आप सरकार के मंत्री थे, संयोग से कभी कभी हम भी थे आपके साथ उस समय भी जब दलीय नेताओं की बैठक में या कार्यमंत्रणा समिति की बैठकों में माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आते थे तो आप तो इसका अनुमोदन करते थे । लगता होगा कि प्रेम जी को यही अच्छा लगता है।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दलः महोदय,लोकतंत्र के विपरीत है महोदय..

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार,मंत्रीः सौहार्दपूर्ण वातावरण बन चुका है महोदय नेता प्रतिपक्ष...

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दलः कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री न आयें, सर्वदलीय बैठक में नहीं आये तो यह संदेश जाता है...

श्री श्रवण कुमार,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल: माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस घटना की निन्दा की है सभी दल के लोगों ने निन्दा किया है कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं अशोक चौधरी जी उनके द्वारा भी निन्दा हुई है । सब जगह निन्दा जब हो रही है और बात साबित हो गयी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में आये और उनकी बर्खास्तगी की घोषणा करें, यही हमारा मांग है।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय,नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात को रखी है और सौहार्दपूर्ण वातावरण सदन के अन्दर बनी है महोदय, मैं आसन से आग्रह करना चाहूंगा महोदय कि सभी दलीय नेताओं से इस संबंध में विचार ले लिया जाय महोदय कि इस इश्यू पर क्या होना चाहिए ।

अध्यक्ष: ठीक है। मतलब सदन की यही राय है।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में चले आये)

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र: गिरिराज सिंह केन्द्रीय मंत्री का क्या बयान आता रहता है...

(व्यवधान)

ये संसदीय परम्परा की बात करते हैं और ये रोज बिहार से आने वाले मंत्री हैं बिहार कोटे से मंत्री है बिहार सरकार और हमारे नेता को रोज असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं । क्या उन्हें ये बर्खास्त करेंगे, बर्खास्त करना चाहेंगे ? हम कहना चाहते हैं बी0जे0पी0 के नेताओं से कि मर्यादा का उल्लंघन न करें और मर्यादा में रहकर संसदीय परम्परा का पालन करें ।

(व्यवधान)

टर्न-3/मधुप/02.03.2017

(व्यवधान)

(इस अवसर पर सत्तापक्ष के कई माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोलने लगे)

अध्यक्ष : क्या चाहते हैं ? आपलोग क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान जारी)

अब सदन की कार्यवाही 2:00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

टर्न-4/आजाद/02.03.2017

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : आपकी बात तो सुनते ही रहते हैं ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री को क्या कठिनाई है, हमलोगों ने मांग किया है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं, क्या कठिनाई है ? पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू जी ने, श्रीमती राबड़ी देवी जी ने भी समर्थन किया कि कार्रवाई हो लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री का ब्यान हमेशा आता है कि हम किसी को बचाते नहीं है और न किसी को फंसाते हैं ? महोदय, हम मांग करते हैं कि जो विडियो वायरल हुआ है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी देख लें, सदन में मंगवाकर विडियो को देख लें और संबंधित मंत्री पर कार्रवाई करें, हमारा महोदय यही अपेक्षा है । पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने और श्रीमती राबड़ी देवी जी ने भी मांग किया है कि कार्रवाई होनी चाहिए तो आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कठिनाई हो रही है? मैं आपके माध्यम से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि क्या कठिनाई है महोदय? महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करते हैं कि लालू जी ने कहा है, राबड़ी जी ने कहा कि कार्रवाई हो और माननीय मुख्यमंत्री जी का ब्यान आता है कि हम न किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं तो आखिर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले मंत्री पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है ? हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि जिस मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री के चित्र पर आदेश दिया कि ऐसे प्रधानमंत्री को जूते से मारो, चप्पल से मारो, लाठी से मारो और ऐसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है । माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कठिनाई है, क्या दिक्कत उनको हो रही है ? जब लालू जी ने कहा है, राबड़ी जी ने भी कहा है कार्रवाई करने के लिए तो कार्रवाई करने में आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या दिक्कत है ? विडियो जो वायरल हुआ है, उसको देख लें सदन में मंगाकर, सभी सदस्यों को देखवा लें और उसपर कार्रवाई हो । महोदय, हमारा आपसे आग्रह है, हमलोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो, आखिर कार्रवाई करने में माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कठिनाई हो रही है, आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करने से क्यों पीछे हट रहे हैं, क्या वजह है? माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने क्या कठिनाई है, सदन में आकर बताये, क्या दिक्कत उन्हें हैं, क्या कठिनाई है, आखिर अब्दुल जलील मस्तान को क्यों संरक्षण देना चाहते हैं,

क्यों बचाना चाहते हैं, क्या कारण है ? जब लालू जी ने भी हमारी मांग का समर्थन किया है, राबड़ी देवी जी ने भी हमारी मांग का समर्थन किया है..........

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति-शांति । माननीय नेता प्रतिपक्ष ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक ही बात को बीस बार रिपीट कर रहे हैं । एक बार जो सवाल उठ जा रहे हैं, उसपर सदन गंभीरता से विचार करे । मैंने आपसे आग्रह किया था कि सभी दलीय नेताओं की बात को सुना जाय और उसके बाद आगे की कार्रवाई हो । सभी दल के नेताओं की बात को सुना जाय, विपक्ष के नेता सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, सिर्फ अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, विपक्ष के नेता को हमलोगों की भी बात को सुननी चाहिए और सदन में जो बात विपक्ष के नेता उठाना चाहते हैं, उसमें हमलोगों की भी बात को सुननी चाहिए । सदन में स्वस्थ्य परम्परा का निर्वहन होना चाहिए , सिर्फ अपनी बात को ही नहीं कहनी चाहिए । एक ही बात को बोले जा रहे हैं । इस तरह से सदन नहीं चलता है, सदन कार्य संचालन नियमावली से चलता है, संविधान से चलता है, ये सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं । ये तानाशाह बनना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के अधिकांश माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर एक साथ खड़े होकर कुछ बोलने लगे)

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जिस तरह से सत्ताधारी दल के मंत्री ने आचरण किया है, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के सदस्य ने जिस तरह से आचरण किया है, उससे देश शर्मसार हुआ है, पूरा बिहार शर्मसार हुआ है । इसलिए महोदय, हम आपसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि लालू जी ने भी, राबड़ी देवी जी ने भी कहा है कि कार्रवाई हो तो कार्रवाई होनी चाहिए । आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कठिनाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई से क्यों पीछे हट रहे हैं, कौन उन्हें रोक रहा है, क्या कठिनाई है, क्या वजह है, क्या कारण है, माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन में आकर बताना चाहिए, स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अगर सबलोग एक-एक करके बोलियेगा तो किसी की बात को कोई सुन भी पायेगा? सामूहिक रूप से सब लोग बोले जा रहे हैं तो इस तरीके से कैसे हो सकता है ? हम तो चाहते हैं कि ललित जी ....

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह का जो ब्यान आया है, वह असंसदीय, अशोभनीय है । गिरिराज सिंह का इस्तीफा करवाना चाहिए, उनको बर्खास्त करवाना चाहिए । मोदी जी को बर्खास्त करना चाहिए, प्रतिपक्ष के नेता, उनको संरक्षण देने का काम ये लोग कर रहे हैं । गिरिराज सिंह का इस्तीफा होना चाहिए, हमलोग मांग करते हैं ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गये)

अध्यक्ष : प्रेम बाबू, अब सदन की कार्यवाही चलने दीजिए न । अभी बजट पर विमर्श होना है, आप उसमें भी सभी बात कह सकते हैं । आप सब बोल सकते हैं ।

अब महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य होना है, आप उसमें अपनी बात रख सकते हैं, आपको भी मौका मिलेगा । अपनी बात इस तरह के माहौल में नहीं, अपनी बात अलग से, जोरदार तरीके से रख सकते हैं तो आप ऐसे अपनी बात क्यों बोलना चाहते हैं कि न कोई आपकी बात सुन सके, न समझ सके और न कुछ बोल सके । आप भी बोलिये और दूसरे को भी सुनिए । कितना अच्छा था आप वहां से बोल रहे थे, फिर इधर चले आये, आप वहां से भी बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे न ? आपलोग वहां जाईए, हम सबको मौका देंगे, सब पार्टी वाले बोलेंगे । आप भी अपनी बात बोलियेगा । अपनी बात नहीं बोलनी है ? अपनी बात आप बोलना ही नहीं चाहते हैं ?

अब वित्तीय कार्य होने दीजिए । अब यह विमर्श का समय है ।

(व्यवधान जारी)

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर सामान्य विमर्श के लिए दिनांक 1 एवं 2 मार्च को तिथि निर्धारित थी । कल 1 मार्च को अन्तराल के बाद सदन की कार्यवाही नहीं हो सकी । इसलिए आज दिनांक 2 मार्च, 2017 को वार्षिक वित्तीय विवरण पर सामान्य विमर्श एवं सरकार का उत्तर होगा । वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के लिए दो घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है और इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	- 40 मिनट
जनता दल यूनाईटेड	- 35 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	- 26 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	- 13 मिनट

सी0पी0आई0(एम0एल0) - 01 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी - 01 मिनट
हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा - 01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी - 01 मिनट
निर्दलीय - 02 मिनट

अब वार्षिक वित्तीय विवरण पर सामान्य विमर्श होगा । माननीय सदस्य श्री मो0 नवाज आलम ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार ।

टर्न-5/शंभु/020217

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, आज सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसपर बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ और आज बजट के पक्ष में बोलने के लिए आसन की तरफ से जो मुझे समय दिया गया है, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि बी0जे0पी0 के लोगों के द्वारा जब-जब बिहार के हित में, बिहार के विकास के हित में, बिहार के गरीबों के हित में जब बजट आता है तो इनके दिलों में जलन पैदा होता है और बिहार के गरीबों के खिलाफ ये हमेशा नरेबाजी करते हैं। यह निश्चित तौर पर आज कहना चाहेंगे कि ये बी0जे0पी0 के लोग बिहार के गरीबों के विकास को देखना नहीं चाहते, बिहार के युवाओं के विकास को देखना नहीं चाहते हैं। बिहार में जब-जब विकास की बातें होती है और विकास के तरफ जब रफ्तार शुरू होता है तो ये सदन को चलने में बाधित करने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से सदन को यह बाधित कर रहे हैं निश्चित तौर पर हम आज धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय वित्त मंत्री जी को कि आपके द्वारा ये गरीब के हित का जो बजट लाया गया है। आज जो युवाओं के हित में बजट लाया गया है, आज युवाओं के हित में बजट लाकर के और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से युवाओं को रोजगार मुहैय्या करने का व्यवस्था किया गया है। निश्चित तौर स्वयं सहायता भत्ता देकर के आज गरीब के बच्चे को कंपीटीशन, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है तो इनके दिलों में जलन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि इनका इतिहास रहा है कि सदन के बाहर कुछ और, और सदन के भीतर कुछ और यह हमेशा असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। बी0जे0पी0 के लोगों के द्वारा जो गरीब के हित में शराब बन्दी हुआ- गांव और गरीब के बीच जो विकास का हालात था, जो विकास दर घटा हुआ था, जो शिक्षा दर घटा हुआ

था, जो आर्थिक दर घटा हुआ था, उसको मजबूत करने का प्रयास जिस तरीके से 1990 के दशक में माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा गरीब के हित में तमाम व्यवस्थाएं की गयी और उस व्यवस्था के तहत गरीबों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, उससे घबड़ाकर के और उसी कड़ी में आज के दिनों में जो महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो बजट में प्रावधान किया गया है गरीब के हित में। आज शराब बन्दी के माध्यम से जो गरीबों के हालात थे वह सुधरने लगे हैं, सामाजिक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण पैदा होने लगे हैं। ये बी0जे0पी0 के लोगों को रसता नहीं है। यह देश को तोड़नेवाली पार्टी है, हमेशा देश को तोड़ने में ये विश्वास रखते हैं। ये सांप्रदयिक पार्टी के लोग निश्चित तौर पर यह आज धर्म निरपेक्षता के आधार पर यह देश विकास के रास्ते पर जा रहा है। धर्म निरपेक्षता के बल पर यह देश आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर अन्य राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसके लिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, हम निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे कि जब भी इस देश में अत्याचार और अनाचार का स्थिति आया है माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी जैसा शक्ति उभरकर के सामने आया हैं। यह देखकर इनके अंदर घबड़ाहट है और इस घबड़ाहट में इनको बिहार की जनता बकसने नहीं जा रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपनी जगह पर जाकर बोलिये न । जगह पर नहीं जाइयेगा तो बोलियेगा कैसे ? यहां से जो बोलियेगा वह लिखायेगा भी नहीं। जगह पर जाकर बोलियेगा तो लिखायेगा भी।

श्री राजेन्द्र कुमार : इस बिहार को बरगलाने का और सदन को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। हम निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे कि बी0जे0पी0 के लोगों के द्वारा असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। हम निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे कि आज जो यह हमारी महागठबंधन की सरकार बजट में प्रावधान की है, बजट में प्रावधान- आज सीमा पर जब जवान मरते हैं तो बी0जे0पी0 के लोग कहते हैं कि सेना मरने के लिए ही भर्त्ती होती है। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे महागठबंधन की सरकार को कि आज सीमा पर या फिर सीमा के बाहर देशहित में अगर कोई लड़ते-लड़ते मरता है तो 11 लाख रूपये का प्रावधान यह महागठबंधन की सरकार ने किया है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जे0पी0 आंदोलन के साथियों को पेंशन की व्यवस्था करके आज देश के हित में, राष्ट्रहित में काम करने के लिए लोगों में उत्सुकता भरने का काम किया गया है। महोदय, हम निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे कि जब-जब इस देश में अत्याचार बी0जे0पी0 के लोगों के द्वारा, देश तोड़ने की व्यवस्था की जाती है तो देश की जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाती है। लेकिन आज की स्थिति में हम कहना चाहेंगे कि एक तरफ हिन्दु मुस्लिम

सिख ईसाई आपस में हैं भाई–भाई– इसका संदेश महागठबंधन के द्वारा जब दिया जा रहा है तो उनको परेशानी हो रही है। यह कभी देश को हिन्दु के नाम पर, कभी हिन्दुत्व के नाम पर केवल माखौल उड़ाते हैं, हिन्दुत्व के लिए कुछ करते नहीं हैं। इनका एक नारा रहता है ये हमेशा हिन्दुत्व के नाम पर देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए बिहार की जनता इनको निश्चित तौर पर सबक सिखलाने का काम करेगी। आज कृषि रोड मैप के माध्यम से किसानों के लिए जो सरकार ने की है, हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय वित्त मंत्री जी को कि आज कृषि के लिए आपने प्रोविजन जो किया है निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है और यह देश ही नहीं दुनिया सराह रही है बिहार की बढ़ती हुई लोकप्रियता को लेकिन बिहार की बढ़ती हुई लोकप्रियता से बी0जे0पी0 वाले घबड़ाहट की स्थिति में हैं। हम निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे कि आज देश के हर क्षेत्र में विकास के लिए हर वर्ग को, हर क्षेत्र को विकास के लिए इंतजाम किया गया है। यह निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि यहां पर इनके द्वारा जो हालात पैदा किया जा रहा है, इनके जवाब में निश्चित तौर पर आज के दिन बिहार हर क्षेत्रों में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आर्थिक हल युवाओं को बल के माध्यम से युवा सशक्त हो रहे हैं और युवा साथी तेजस्वी यादव जो इस राज्य ही नहीं दुनिया में और इस देश के युवा इनके फैन होते जा रहे हैं, लोग उनको जानने लगे हैं और उनपर विश्वास करने लगे हैं, इसलिए इनकी घबड़ाहट बढ़ती जा रही है और बाहर के प्रदेशों में उनकी हार सुनिश्चित होने लगी है तो ये लोग घबड़ाहट में सदन को इस तरह करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। कुशल योजना के तहत आप जानते हैं कि हर क्षेत्र में युवाओं के लिए अनेक प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, आइ0टी0आइ0 कॉलेज हमारी सरकार ने खोलने का प्रयास किया है। आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं ये बी0जे0पी0 वाले भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ये भ्रष्टाचार की बातें करते हैं हमारी सरकार में महागठबंधन की सरकार में कानून का राज है और गलत करनेवाले पदाधिकारी किसी हालत में बचकर नहीं जाते हैं। इसका उदाहरण है कि इस राज्य में कोई भी पदाधिकारी अगर गलत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर दंडित हो रहे हैं। इस सुशासन की सरकार में जो भी गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। आज हम कहना चाहेंगे कि पुलिस को सशक्त करने के लिए सभी राज्यों में पुलिस भवन बनाया जा रहा है, हर जगह पुलिस को सशक्त करने के लिए बजट में प्रोविजन किया गया है। यह देखकर बी0जे0पी0 के अंदर घबड़ाहट है। हम कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी के पेंशनधारी के पौत्री और नतिनी को शादी करने पर 51 हजार का प्रोविजन उनकी शादी के लिए करके हम धन्यवाद देना चाहेंगे वित्त मंत्री जी को और हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय तेजस्वी यादव जी को और नीतीश कुमार जी को कि आपने स्वतंत्रता सेनानी के

पौत्री और नतिनी के लिए 51 हजार रूपया देकर के उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाने का प्रयास और मदद करने का काम किया है। इसलिए भरत की जनता के तरफ से हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा जो स्थिति आज देशहित में किया गया है वह काबिले तारीफ है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य राजेन्द्र जी, अब आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार : आज अपना राजस्व 2015-16 में 25 हजार 449 करोड़ रूपया है जो विगत वर्ष से 22.65 प्रतिशत अधिक है। जो बढ़कर 2016-17 में 29.93 करोड़ रूपया होने का अनुमान है। यह आर्थिक विकास देखकर निश्चित रूप से बी0जे0पी0 के लोगों में घबड़ाहट है और यह घबड़ाहट आनेवाले दिनों में पूरे बिहार की जनता और देश की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। आज देश में जो आर्थिक, शैक्षणिक और देश में रोड मैप के माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय तेजस्वी यादव जी को कि बाहर से टेक्नोलोजी लाकर के पूरे बिहार में नये तकनीक का रोड बनाने का काम किया है।

अध्यक्ष : ठीक है, आप समाप्त कीजिए।

श्री राजेन्द्र कुमार : ये बी0जे0पी0 के लोग सांप्रदायिकता में विश्वास रखते हैं, देश को तोड़ने में विश्वास रखते हैं, इनमें घबड़ाहट है कि सांप्रदायिक ताकत के लोग यहां पर अमन-चैन का माहौल है, तमाम क्षेत्रों में और हिन्दु मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई-भाई माहौल पैदा हो रहा है।

अध्यक्ष : राजेन्द्र जी, आपका भाषण समाप्त हुआ ।

अब सभा की कार्यवाही 3:30 बजे अप0 तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न-6/अशोक/02.03.2017

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, सरकार को कहा जाय..........

(इस अवसर पर विपक्ष के मा0 सदस्यगण वेल में आकर बैठ गये)

अध्यक्ष : सरकार को ही कहने के लिए कह रहे हैं । वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर सरकार का वक्तव्य । माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप अवगत हैं कि 27 फरवरी,2017 को बजट प्रस्तुत किया गया और बजट पर हमें अपेक्षा थी कि खास करके विरोधी दल के नेता और विरोधी दल के सदस्य इस पर चर्चा करेंगे, कुछ अपना मूल्यवान सुझाव देंगे ताकि आगे के लिए उनके अनुभव का हम फायदा उठा सकें । मगर अफसोस उनका जो फिक्स्ड एजेंडा हैं उस फिकस्ड एजेंडा के तहत उन्होंने बजट भाषण पर अपना वक्तव्य देना हलका समझा और अपने एजेंडा के लिए वो जो हैं अपनी बातों को अपना जिस रूप में किये ।

महोदय, बजट भाषण के क्रम में सदन के माननीय सदस्यों, मीडिया और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया देखने एवं सुनने को मिली, विपक्ष की ओर से कहा गया कि बजट Lack lustre है ; बजट का कोई फोकस नहीं है; विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम प्रावधान किया गया है; कृषि, स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ऊर्जा, पर्यटन ऐसे कई महत्वपूर्ण विभागों के लिए तुलनात्मक रूप से 2017-18 वित्तीय वर्ष के बजट में कम महत्व दिया गया है; Budget At a glance पेश नहीं किया गया है, जब कि महोदय Budget At a glance पेश किया था, मेरा बजट भाषण बहुत छोटा हैं इत्यादि, इत्यादि । हमारे विरोध पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट भाषण के Lack lustre होने की बात हैं, Lack lustre का अर्थ हुआ लोक लुभावन नहीं होना । लोक-लुभावन बनाने के लिए कई ऐसे वायदे करने होते हैं जो सुनने में अच्छा लगे भले ही इसका

कार्यान्वयन न हो, उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जेब में 15 लाख रू0 आ जायेगा, कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, करोड़ो रोजगार का प्रति वर्ष सृजन होगा और अंत में, बिहार राज्य को 1 लाख 85 हजार करोड़ रूपये का पैकेज दिया जायेगा, हम सभी जानते हैं कि उपरोक्त घोषणाओं और भाषणों का क्या हश्र हुआ है ।

अर्थशास्त्री एवं प्रोफेसर डॉ ज्ञानचंद ने कहा था कि वादों की हरित क्रांति के कारण ही समाज में विषमता फैलेगी और समाज विरोधी ताकतों के द्वारा ही समाजवाद आयेगा । मैं समझता हॅं कि प्रो0 ज्ञानचंद के इस Statement की संजीदगी सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से समझ रहे हैं । आज जो सामाजिक तनाव है, नक्सलवादी गतिविधियॉं हैं, समाज में टूटन दिखाई पड़ रही है, वह ऐसे ही वादों की हरित क्रंति के ख्याली पुलाव और हवाई घोषणाओं के कारण हुई है । मैं इससे बचता हूॅं और बचता रहूॅंगा ।

माननीय बिहार विधान परिषद् के प्रतिपक्ष के नेता, जो पूर्व वित्तमंत्री हैं, ने कहा कि राज्य सरकार ने यह नहीं बतमाया है कि बजट के लिए राशि कहॉं से प्राप्त होगी । उन्होंने यह भी कहा कि Budget At a Glance पेश नहीं की गई है ।

(व्यधान जारी)

मैं माननीय सदस्यों को "बजट का सार" किताब, जो हरे रंग की है, दिखाना चाहूंगा । संभवत: प्रतिपक्ष के नेता ने इस किताब को नहीं देखा हैं । इस किताब के पृष्ठ-1 पर यह स्पष्ट किया गया है कि बजट के लिए राशि किस-किस स्त्रोत से प्राप्त होनी हैं । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूॅं कि 2017-18 के बजट में कुल व्यय 1,60,085.69 करोड़ रूपये का है जबकि कुल प्राप्तियां उससे ज्यादा 1,61,039. 09 करोड़ रूपये की अनुमानित हैं । इस कुल प्राप्ति में केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा मद में 65,326.34 करोड़ रूपये, राज्य के अपने कर राजस्व में 32,001.12 करोड़ रूपये, राज्य के गैर कर राजस्व मद में 2,874.96 करोड़ रूपये, केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान मद में 36,956.00 करोड़ रूपये एवं पूजीगत प्राप्तियॉं मद में 23,880 करोड़ रूपये अनुमानित है ।

माननीय नेता विपक्ष ने बजट के संदर्भ में यह कहा कि बजट में कोई फोकस नहीं है । मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के माननीय नेतागण ने मेरे बजट भाषण पर ध्यान से न तो सुना और न तो देखा । मेंने अपने बजट भाषण के दौरान यह बताया था कि वर्ष 2017-18 के बजट का मुख्य फोकस निम्नलिखित है : 1.विकास, 2. गरीबी उन्मूलन एवं 3. वित्तीय स्थायित्व ।

जहॉं तक विकास का प्रश्न है हमने वार्षिक स्कीम वर्ष 2016-17 में 71501.84 करोड़ रूपये से बढ़ा कर वर्ष 2017-18 में 80891.61 करोड़ रूपये किया है जो पूर्व वर्ष से 13.13 प्रतिशत यानी 9389.77 करोड़ रूपये अधिक हैं ।

जहां तक गरीबी उन्मूलन की बात है, आप सभी जानते हैं कि बिहार की 89 प्रतिशत जनसंख्या गॉंव में रहती है तथा 76 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अत: विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट में पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं । ग्रामीण विकास विभाग का कुल बजट प्रावघन 9717.48 करोड़ रूपये का है जो पूर्व वर्ष की तुलना में 76.36 प्रतिशत अधिक है । इसी प्रकार ग्रामीण कार्य विभाग का कुल बजट प्रावधान 9518.05 करोड़ रूपये का है जो पूर्व वर्ष की तुलना में 33.11 प्रतिशत है और पंचायती राज विभाग का कुल बजट प्रावधान 8694.43 करोड़ रूपये का है जो पूर्व वर्ष की तुलना में 21.03 प्रतिशत अधिक है । क्रमश:

टर्न-07:ज्योति

02-03-2017 क्रमश:

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, मंत्री: विपक्ष के माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि आर्थिक सवेक्षण 2016-17 में यह बताया गया है कि कृषि के विकास दर में कमी आयी है एवं बजट में इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी है इस संदर्भ में माननीय सदस्यों से मेरा यह कहना है कि जैसा कि आप जानते हैं कि विगत दो तीन वर्षों से अनुकूल वर्षा नहीं हुई है इससे संपूर्ण देश के कृषि दर में कमी आयी है किन्तु मैं माननीय सदस्यों को हर्ष के साथ यह कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2016 में वर्षा अपने राज्य में प्रचुर मात्रा में हुई है और बिहार में खाद्यान्न का बंपर उत्पादन हुआ है । कृषि कार्य को वर्षा के उथल पुथल से मुक्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सिंचाई पर आवश्यक ध्यान दिया जाय । इसके लिए जल संसाधन विभाग के बजट में कुल 3814.17 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है जो पूर्व वर्ष से 67.35 प्रतिशत अधिक है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनॉंक 28 फरवरी 2017 को दिए गए अपने भाषण में कहा था कि राज्य सरकार सभी चालू कार्यक्रमों यथा कृषि रोड मैप, मानव संसाधन विकास मिशन एवं 7 निश्चय कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य का विकास सुनिश्चित करने हेतु कृतसंकल्पित है ।

कृषि रोड मैप - कृषि का विकास सरकार की प्राथमिकता है । कृषि रोड मैप के अधीन खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिए श्री-विधि से धान की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु लघु तथा सीमान्त किसानों एवं कृषि मजदूरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है । धान की

पैदावार को बढ़ाने के लिए आधुनिक यंत्र खासकर पैडी ट्रांसप्लांटर तथा पैडी ड्रम सीडर को बढ़ावा देने एवं जीरो-टिलेज विधि से गेहूँ की खेती को प्रोत्साहित करने, कस्टम हायरिंग केन्द्र (कृषि यंत्र बैंक) का विस्तार करने एवं प्रत्येक किसान को 2 वर्षों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है । 362 प्रखंडों में ई-किसान भवन के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है । कृषि शिक्षा के प्रति उन्मुख करने के लिए प्रत्येक मेधावी छात्र को 2,000 रुपये प्रतिमाह स्टाईपेंड तथा 6,000 रुपये प्रति वर्ष पुस्तक आदि खरीदने के लिए सहायता दी जा रही है ।

जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, अभी तक 18 हजार 730 वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना की गयी है । 107 किसानों को गोबर गैस की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है ।

कृषि रोड मैप कार्यक्रम का लाभ उठाकर हमारे मेहनती किसान चाव, गेहूँ एवं मक्का की उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि कर राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गए हैं ।

वर्ष 2016-17 में चावल का उत्पादन द्वितीय अग्रिम पूर्वानुमान के अनुसार 84 लाख 90 हजार मेट्रिक टन होने का आकलन किया गया है, जो एक रिकॉर्ड है ।

जहाँ तक मानव विकास का प्रश्न है, हमारे बजट में शिक्षा विभाग के लिए रिकॉर्ड संसाधन उपलब्ध कराये गए हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए शिक्षा विभाग का बजट उपबंध 25251.39 करोड़ रुपये का किया गया है । छात्रवृति एवं पोशाक मद में शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं समाज कल्याण विभाग में कुल 2,196.97 करोड़ रुपये की राशि का उपबंध किया गया है ।

जहाँ तक 7 निश्चय कार्यक्रम का प्रश्न है इसके अंतर्गत (1)आर्थिक हल, युवाओं को बल-स्टूडेन्ड क्रेडिट कार्ड योजना-इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु स्टूडेन्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है जिसमें 4 लाख रुपये तक के ऋण बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार की गारंटी के विरुद्ध विद्यार्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं । यह योजना आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित विद्यार्थियों के लिए सहायक साबित होगी । साथ ही इससे उच्च शिक्षा में नामांकन दर के प्रतिशत में भी सुधार आयेगा । मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना - यह योजना 2 अक्तूबर 2016 से प्रारंभ है । इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवकों को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1000 रुपये की दर से स्वयं सहायता भत्ता 2 वर्षों के लिए दी जा रही है ।

कुशल युवा कार्यक्रम - यह योजना 2 अक्तूबर 2016 से प्रारंभ है । इस योजना के तहत 15 से 25 वर्ष के युवा जो मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है उन्हें भाषा, कम्प्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है ।

उपरोक्त आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत उपरोक्त तीनों योजनाओं के कार्यान्वयन एवं ऑन लाईन आवेदकों का निबंधन एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र की स्थापना की गयी है । बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2016- राज्य में युवाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए यह नीति लागू की गयी है । सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई-फाई -राज्य के युवाओं को ई-गवर्नेंश से जोड़ने के लिए सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई-फाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।

हर घर बिजली लगातार - इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना लागू की गयी है । इसके अन्तर्गत आगामी 2 वर्षों में राज्य सरकार अपने संसाधनों से सभी घरों तक मीटर के साथ विद्युत संबंध प्रदान करायेगी । मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के लिए वर्ष 2017-18 में 750 करोड़ रुपये का बजट उपबंध उर्जा विभाग की मांग में किया गया है ।

हर घर नल का जल - इस निश्चय का उद्देश्य बिहार के हर नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया है । इस निश्चय को पूरा करने हेतु 4 योजनाएं यथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेय जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना लागू की गयी है ।

क्रमशः

टर्न-8/02.3.2017/बिपिन

(व्यवधान)

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण वेल में पूर्व से बैठे हुए थे)

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्रीः क्रमशः हर घर नल का जल -

इस निश्चय का उद्देश्य बिहार के हर नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है । इस निश्चय को पूरा करने हेतु 4 योजनाएं, यथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र

निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना लागू की गयी है ।

हर घर नल का जल कार्यक्रम का कार्यान्वयन पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, आवास विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से किया जा रहा है । जैसा कि मैंने पहले बोला था, पंचायतों का प्रावधान 21.03 प्रतिशत से बढ़ाकर 8694.43 करोड़ रूपये, नगर विकास एवं आवास विभाग का प्रावधान 27.15 प्रतिशत बढ़ाकर 4335.01 करोड़ रूपये एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का प्रावधान 38.71 प्रतिशत बढ़ाकर 2434.41 करोड़ रूपये किये गये हैं ।

(व्यवधान जारी)

हर घर तक पक्की गली-नालियाँ -

इस निश्चय के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के उपरांत, शेष बचे राज्य के सभी सम्पर्क विहिन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जाना तथा सभी गॉव एवं शहरों में गली-नाली का निर्माण कराया जाना है । इस निश्चय को पूरा करने हेतु 3 योजनाएं प्रारंभ की गयी है, यथा- ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना । इन सभी कार्यक्रमों पर स्थानीय निकायों के माध्यम से राशि का व्यय किया जा रहा है जिसके लिए पर्याप्त राशि का बजट में उपबंध किया गया है । यह निश्चय अगले चार वर्षों में पूरे किए जाने का लक्ष्य है ।

शौचालय निर्माण घर का सम्मान -

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग एवं शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत खुले में शौच से मुक्त, स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए राज्य के प्रत्येक घर में शौचालय की व्यवस्था की जानी है । इस निश्चय को पूरा करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दो योजनाएं यथा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं शौचालय निर्माण (शहरी क्षेत्र) योजना है । इसके लिए भी बजट में राशि का पर्याप्त उपबंध किया गया है ।

(व्यवधान जारी)

आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, महोदय, सात निश्चय के बारे में जो लिखित है वह हम दे देते हैं महोदय । अगर वित्तीय स्थायित्व के संबंध में भी महोदय, हमारा वित्तीय प्रबंधन बेटर है, यह भी हमने अपने इसमें किया है महोदय और साथ-ही-साथ, पर्यटन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, स्वास्थ्य विभाग, सारी बातें, योजना एवं विकास विभाग, श्रम संसाधन विकास विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग ।

महोदय, नेता प्रतिपक्ष जो खुद वित्त मंत्री रहे हैं । उनको आइना नहीं दिखता है और आप सभी को याद होगा कि 2015 के केंद्र सरकार के बजट के पहले एक बेवसाइट में व्यंग्य छपा था जिसका शीर्षक था 'बजट आलोचना के दस आसान तरीके।' बजट में केवल बातें हैं, कोई ठोस चीज नहीं है, केन्द्र के बारे में, बजट में कोई सुधार जैसी बातें नहीं है । महोदय, मैं अपना यह सारा लिखित भाषण, आपकी अनुमति हो तो मैं इसे सदन के पटल पर रख देता हूं ।

(परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : ठीक है ।

(व्यवधान जारी)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन और माननीय सदस्यों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया और व्यवहारिक सुझावों का सरकार कद्र करती है, मगर अफसोस कि माननीय विपक्ष के नेताओं ने इस डिबेट में भाग ही नहीं लिया । उनके लिए प्रायरिटी अपना राजनीतिक एजेंडा है, न कि बजट भाषण । महोदय, मैं अंत में यह कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि -

"मेरी जिन्दगी यही है कि सबों को फैज पहुंचे,
मैं चिराग-रहगुजर हूं, मुझे शौक से जलाओ"

धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सरकार का वक्तव्य समाप्त हुआ । वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर सामान्य विमर्श भी समाप्त हुआ ।

माननीय सदस्यगण, अब नेता प्रतिपक्ष के साथ सभी माननीय सदस्यों से जो वेल में बैठे हैं, उनसे आसन की तरफ से आग्रह है कि कृपया अपने-अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएं । सदन के सुव्यवस्थित संचालन में आपके सहयोग की अपेक्षा रखता है आसन । यह सदन आप सबों का भी है । आप अगर अपनी जगह से कहेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे । सब लोग मिल कर बोल रहे हैं । मुख्यमंत्री जी भी आपकी बात समझना चाह रहे थे, बार-बार कह रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : हमने कहा कि वेल में बैठे हुए हैं लेकिन पानी इनको देना चाहिए था आपको पीने के लिए, सबका गला फँसा हुआ था । नारा लगाने में दिक्कत हो रही थी। पानी पिलवा दीजिए इनको ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: आज दिनांक 02 मार्च, 2017 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-51 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिए जाएं ।

(सदन की सहमति हुई)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपने आसन से जाकर बोलिए न, वहीं से बोल रहे हैं ।

(इस अवसर पर श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल अपनी सीट पर आ गए)

श्री प्रेम कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूं ...

अध्यक्ष : अच्छा, आप बताइये प्रेम बाबू कि आप ही के माननीय सदस्य सदन की व्यवस्था में बाधा डालते हैं और आप ही व्यवस्था की बात उठाते हैं । ऐसे में कैसे होगा?

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, हम तो आसन को सहयोग कर रहे हैं महोदय ।

अध्यक्ष : पहले इनको कहिए । पहले अपने सदस्यों को बुला लीजिए न ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : बुलवा लेते हैं महोदय । महोदय, हम आसन को सहयोग करना चाहते हैं महोदय । माननीय मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं महोदय...

अध्यक्ष : अब अब सभा की बैठक शुक्रवार दिनांक 03मार्च, 2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

***

परिशिष्ट

माननीय अध्यक्ष महोदय,

- बजट भाषण के क्रम में सदन के माननीय सदस्यों, मीडिया और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया देखने एवं सुनने को मिली, विपक्ष की ओर से कहा गया है कि :–

  (क) बजट Lack lustre है;

  (ख) बजट का कोई फोकस नहीं है;

  (ग) विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम प्रावधान किया गया है;

  (घ) कृषि, स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ऊर्जा, पर्यटन ऐसे कई महत्वपूर्ण विभागों के लिए तुलनात्मक रूप से 2017–18 वित्तीय वर्ष के बजट में कम महत्व दिया गया है;

  (ङ) Budget At a glance पेश नहीं किया गया है;

  (च) मेरा बजट भाषण बहुत छोटा है इत्यादि ।

- अध्यक्ष महोदय जहां तक बजट भाषण के Lack lustre होने की बात है Lack lustre का अर्थ हुआ लोक लुभावन नहीं होना । लोक–लुभावन बनाने के लिए कई ऐसे वायदे करने

होते हैं जो सुनने में अच्छा लगे भले ही इसका कार्यान्वयन न हो, उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जेब में 15 लाख रू0 आ जायेगा, कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, करोड़ों रोजगार का प्रतिवर्ष सृजन होगा और अंत में, बिहार राज्य को 1 लाख 85 हजार करोड़ रूपये का पैकेज दिया जायेगा । हम सभी जानते हैं कि उपरोक्त घोषणाओं और भाषणों का क्या हश्र हुआ है ।

- अर्थशास्त्री एवं प्रोफेसर डॉ0 ज्ञानचंद ने कहा था कि वादों की हरित क्रांति के कारण ही समाज में विषमता फैलेगी और समाज विरोधी ताकतों के द्वारा ही समाजवाद आयेगा । मैं समझता हूं कि प्रो0 ज्ञानचंद के इस Statement की संजीदगी सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आज जो सामाजिक तनाव है, नक्सलवादी गतिविधियाँ हैं, समाज में टूटन दिखाई पड़ रही है, वह ऐसे ही वादों की हरित क्रांति के ख्याली पुलाव और हवाई घोषणाओं के कारण हुई है । मैं इससे बचता हूँ और बचता रहूँगा ।
- माननीय बिहार विधान परिषद् के प्रतिपक्ष के नेता, जो पूर्व वित्तमंत्री हैं, ने कहा है कि राज्य सरकार ने यह नहीं बताया है कि बजट के लिए राशि कहाँ से प्राप्त होगी । उन्होंने यह

भी कहा कि Budget At a Glance किताब पेश नहीं की गयी है ।

मैं माननीय सदस्यों को **"बजट का सार"** किताब, जो हरे रंग की है, दिखाना चाहूँगा । संभवतः प्रतिपक्ष के नेता ने इस किताब को नहीं देखा है । इस किताब के पृष्ठ 1 पर यह स्पष्ट किया गया है कि बजट के लिए राशि किस–किस स्त्रोत से प्राप्त होनी है । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 2017–18 के बजट में कुल व्यय 1,60,085.69 करोड़ रूपये का है जबकि कुल प्राप्ति उससे ज्यादा 1,61,039.09 करोड़ रूपये की अनुमानित है । इस कुल प्राप्ति में केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा मद में 65,326.34 करोड़ रूपये, राज्य के अपने कर राजस्व में 32,001.12 करोड़ रूपये, राज्य के गैर कर राजस्व मद में 2,874.96 करोड़ रूपये, केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान मद में 36,956.00 करोड़ रूपये एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ मद में 23,880.68 करोड़ रूपये अनुमानित है।

- माननीय नेता विपक्ष ने बजट के संदर्भ में यह कहा कि बजट में कोई फोकस नहीं है।

मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के माननीय नेतागण ने मेरे बजट भाषण पर ध्यान नहीं दिया है। मैंने अपने बजट भाषण के दौरान यह बताया था कि वर्ष 2017–18 के बजट का मुख्य फोकस निम्नलिखित है–

(क) विकास

(ख) गरीबी उन्मुलन

(ग) वित्तीय स्थायित्व

(क) विकास

- जहाँ तक विकास का प्रश्न है हमने वार्षिक स्कीम वर्ष 2016–17 में 71501.84 करोड़ रूपये से बढ़ा कर वर्ष 2017–18 में 80891.61 करोड़ रूपये किया गया है जो पूर्व वर्ष से 13.13 प्रतिशत यानि 9389.77 करोड़ रूपये अधिक है।

(ख) गरीबी उन्मूलन

- आप सभी जानते हैं कि बिहार की 89 प्रतिशत जनसंख्या गाँव में रहती है तथा 76 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अतः विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट में पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। ग्रामीण विकास विभाग

का कुल बजट प्रावधान 9717.48 करोड़ रूपये का है जो पूर्व वर्ष की तुलना में 76.36 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार ग्रामीण कार्य विभाग का कुल बजट प्रावधान 9518.05 करोड़ रूपये का है जो पूर्व वर्ष की तुलना में 33.11 प्रतिशत है और पंचायती राज विभाग का कुल बजट प्रावधान 8694.43 करोड़ रूपये का है जो पूर्व वर्ष की तुलना में 21.03 प्रतिशत अधिक है।

➢ विपक्ष के माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17 में यह बताया गया है कि कृषि के विकास दर में कमी आयी है एवं बजट में इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

इस संदर्भ में मेरा माननीय सदस्यों से यह कहना है कि जैसा कि आप जानते हैं विगत दो–तीन वर्षों से अनुकूल वर्षा नहीं हुई है इससे सर्म्पूण देश के कृषि विकास दर में कमी आयी है किन्तु मैं माननीय सदस्यों को हर्ष के साथ यह कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2016 में वर्षा प्रचुर मात्रा में हुई है और बिहार में खाद्यान्न का बम्पर उत्पादन हुआ है।

कृषि कार्य को वर्षा के उथल–पुथल से मुक्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सिंचाई पर आवश्यक ध्यान दिया जाय। इसके लिए जल संसाधन विभाग के बजट में कुल 3814.07 करोड़ रूपये का उपबंध किया गया है जो पूर्व वर्ष से 67.35 प्रतिशत अधिक है।

- मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक–28 फरवरी 2017 को दिये अपने भाषण में कहा था कि राज्य सरकार सभी चालू कार्यक्रमों यथा कृषि रोड मैप, मानव संसाधन विकास मिशन एवं 7 निश्चय कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य का विकास सुनिश्चित करने हेतु कृतसंकल्पित है।

कृषि रोड मैप– कृषि का विकास सरकार की प्राथमिकता है। कृषि रोड मैप के अधीन खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिए श्री–विधि से धान की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु लघु तथा सीमान्त किसानों एवं कृषि मजदूरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। धान की पैदावार

को बढ़ाने के लिए आधुनिक यंत्र खासकर पैडी ट्रांसप्लांटर तथा पैडी ड्रम सीडर को बढ़ावा देने एवं जीरो–टिलेज विधि से गेहूँ की खेती को प्रोत्साहित करने, कस्टम हायरिंग केन्द्र (कृषि यंत्र बैंक) का विस्तार करने एवं प्रत्येक किसान को 2 वर्षों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। 362 प्रखंडों में ई–किसान भवन के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। कृषि शिक्षा के प्रति उन्मुख करने के लिए प्रत्येक मेधावी छात्र को 2,000 रूपये प्रतिमाह स्टाईपेंड तथा 6,000 रूपये प्रति वर्ष पुस्तक आदि खरीदने के लिए सहायता दी जा रही है।

जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, अभी तक 18 हजार 730 वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना की गयी है। 107 किसानों को गोबर गैस की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

कृषि रोड मैप कार्यक्रम का लाभ उठाकर हमारे मेहनती किसान चावल, गेहूँ एवं मक्का की उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि कर राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गये हैं।

वर्ष 2016–17 में चावल का उत्पादन द्वितीय अग्रिम पूर्वानुमान के अनुसार 84 लाख 90 हजार मेट्रिक टन होने का आंकलन किया गया है, जो एक रिकॉर्ड है।

- जहाँ तक मानव विकास का प्रश्न है, हमारे बजट में शिक्षा विभाग के लिए रिकॉर्ड संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए शिक्षा विभाग का बजट उपबंध 25251.39 करोड़ रूपये का किया गया है। छात्रवृति एवं पोशाक मद में शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं समाज कल्याण विभाग में कुल 2,196.97 करोड़ रूपये की राशि का उपबंध किया गया है।

- जहाँ तक 7 निश्चय कार्यक्रम का प्रश्न है इसके अंतर्गत

(1) आर्थिक हल, युवाओं को बल–

(क) स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना– इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है जिसमें 4 लाख रूपये तक के ऋण बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार

की गारंटी के विरूद्ध विद्यार्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। यह योजना आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित विद्यार्थियों के लिए सहायक साबित होगी। साथ ही इससे उच्च शिक्षा में नामांकन दर के प्रतिशत में भी सुधार आयेगा।

(ख) मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना– यह योजना 2 अक्टूबर 2016 से प्रारंभ है। इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवकों को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1000 रूपये की दर से स्वयं सहायता भत्ता 2 वर्षों के लिए दी जा रही है।

(ग) कुशल युवा कार्यक्रम– यह योजना 2 अक्टूबर 2016 से प्रारंभ है। इस योजना के तहत 15 से 25 वर्ष के युवा जो मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट उर्त्तीण है उन्हें भाषा, कम्प्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है।

उपरोक्त आर्थिक हल युवाओं के बल के अन्तर्गत उपरोक्त तीनों योजनाओं के कार्यान्वयन एवं ऑन लाईन

आवेदकों का निबंधन एवं अग्रत्तर कार्रवाई हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र की स्थापना की गयी है।

(घ) बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2016– राज्य में युवाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए यह नीति लागू की गयी है।

(ङ) सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई–फाई– राज्य के युवाओं को ई–गर्वनेंस से जोड़ने के लिए सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई–फाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) हर घर बिजली लगातार–

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना लागू की गयी है। इसके अन्तर्गत आगामी 2 वर्षों में राज्य सरकार अपने संसाधनों से सभी घरों तक मीटर के साथ विद्युत संबंध प्रदान करायेगी। मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के लिए वर्ष 2017–18 में 750 करोड़ रूपये का बजट उपबंध ऊर्जा विभाग के मांग में किया गया है।

(3) हर घर नल का जल–

इस निश्चय का उद्देश्य बिहार के हर नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इस निश्चय को पूरा करने हेतु 4 योजनाएं यथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना लागू की गयी है।

हर घर नल का जल कार्यक्रम का कार्यान्वयन पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले बोला था पंचायतों का प्रावधान 21.03 प्रतिशत बढ़ाकर 8694.43 करोड़ रूपये, नगर विकास एवं आवास विभाग का प्रावधान 27.15 प्रतिशत बढ़ाकर 4335.01 करोड़ रूपये एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का प्रावधान 38.71 प्रतिशत बढ़ाकर 2434.41 करोड़ रूपये किया गया है।

(4) हर घर तक पक्की गली–नालियाँ–

इस निश्चय के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के उपरांत, शेष बचे राज्य के सभी सम्पर्क विहिन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जाना तथा सभी गाँव एवं शहरों में गली–नाली का निर्माण कराया जाना है। इस निश्चय को पूरा करने हेतु 3 योजनाएं प्रारंभ की गयी है यथा–ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना। इन सभी कार्यक्रमों पर स्थानीय निकायों के माध्यम से राशि का व्यय किया जा रहा है जिसके लिए पर्याप्त राशि का बजट में उपबंध किया गया है। यह निश्चय अगले चार वर्षों में पूरे किये जाने का लक्ष्य है।

(5) शौचालय निर्माण घर का सम्मान–

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग एवं शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत खुले में शौच से मुक्त, स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए राज्य के प्रत्येक घर

में शौचालय की व्यवस्था की जानी है। इस निश्चय को पूरा करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दो योजनाएं यथा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं शौचालय निर्माण (शहरी क्षेत्र) योजना है। इसके लिए भी बजट में राशि का पर्याप्त उपबंध किया गया है।

(6) आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार–

इस निश्चय के अन्तर्गत राज्य के सभी सेवा संवर्गों की सीधी नियुक्ति में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था स्वीकृत की गयी है।

(7) अवसर बढ़े, आगे पढ़ें–

इस निश्चय के अन्तर्गत राज्य में तकनीकी शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने एवं युवाओं को राज्य में ही तकनीकी शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है। इसके लिए प्रत्येक जिला में जी०एन०एम० स्कूल, पैरा मेडिकल संस्थान, पॉलिटेकनीक संस्थान, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल में ए०एन०एम० स्कूल एवं औद्योगिक

प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना तथा राज्य में 5 और नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का लक्ष्य है।

(ग) **वित्तीय स्थायित्व**

राज्य की वित्तीय स्थिति बेहतर है जो कि निम्नलिखित राजकोषीय उपलब्धियों द्वारा प्रदर्शित हो रही है–

I. वर्ष 2015–16 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.48 प्रतिशत रहा जो कि 3 प्रतिशत की निर्धारित अधिसीमा के अधीन है ।

II. वर्ष 2015–16 में लोक ऋण एवं अन्य दायित्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 23.92 प्रतिशत रहा जो कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 25 प्रतिशत तक अधिकतम रहना चाहिए ।

III. वर्ष 2015–16 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 7.38 प्रतिशत रहा जो कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 10 प्रतिशत तक अधिकतम रहना चाहिए ।

IV. राज्य सरकार ने विगत पाँच वर्षों में राजस्व अधिक्य प्राप्त किया । वर्ष 2015–16 में राजस्व अधिक्य 12507.16 करोड़

रूपये रहा जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.57 प्रतिशत है जो कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में वर्ष 2008–09 से राजस्व अधिक्य बनाये रखना है ।

- सरकार में आप भी रहे हैं और हम भी हैं । इसके काम करने के तरीके से दोनों वाकिफ हैं । आवश्यकताओं और साधनों को व्यवस्थित करने के प्रयास को ही बजट exercise कहा जाता है । ऐसी कोई राज्य सरकार नहीं है जिसके बजट में केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली राशि का महत्व नहीं होता है । उत्तर–दक्षिण–पूरब–पश्चिम किधर भी झाँक लें, एक भी ऐसा राज्य नहीं मिलेगा जो केन्द्र सरकार से बिना राशि प्राप्त किये अपनी सरकार चला ले । इसके बावजूद बिहार सरकार पर यह तोहमत लगाना कि हम केन्द्र सरकार की इनायत पर हैं, यह Intellectual Dishonesty है अगर मैं कहूँ कि यह Intellectual Bankruptcy है तो विपक्ष के सदस्य इसे अन्यथा ले लेंगे । यह हमारी मजबूरी है कि संसदीय मर्यादा के तहत सच को सच नहीं कह पा रहे हैं ।

- अगर आंकड़ों की बात करूँ तो राज्य सरकारों को अब तक यह नहीं बताया गया है कि नोटबंदी के फलस्वरूप कितने पुराने नोट बैंकों में जमा हुए और कितना कालाधन पता चला। डिमोनेटाईजेशन के उद्देश्य की बात मैं नहीं करता, लेकिन किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने में इससे अधिक लापरवाही, व्यवस्था का अभाव, अराजकता और आम लोगों को कठिनाई का नमूना, कम–से–कम, भारत में तो नहीं ही मिलेगा। यह सबकुछ केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऐसे विशेषज्ञ संस्थाओं की देख–रेख में हुआ है। इसके बावजूद विपक्ष हम पर व्यवस्था, कार्यप्रणाली, स्पष्ट उद्देश्य और समय सीमा ऐसे बिन्दु पर कुछ कहें तो देहाती भाषा में हम यही कहेंगे कि ''सूप हँसे चलनी को जिसमें हजारों छेद।''
- बजट भाषण छोटा हो या बड़ा इसका महत्व नहीं है जितना महत्व इसका है कि सरकार के कार्यक्रम उद्देश्य और संकल्प की स्पष्ट जानकारी दी गई है या नहीं । राजनीतिक भाषा में यों समझ लें कि चुनाव रैली में लाखों की भीड़ हो लेकिन पार्टी का उम्मीदवार हार जाये तो ऐसी भीड़ बेमानी होती है।

- माननीय अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ विभागों के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कम राशि प्रावधानित करने पर प्रश्न उठाया है। मैं सदन को वर्त्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्ष 2017–18 में कुछ विभागों के बजट प्रावधान कम होने के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा–

- **ऊर्जा विभाग–** वर्ष 2016–17 में 14367.85 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2017–18 में 10905.03 करोड़ रूपये अर्थात 3462.02 करोड़ रूपये की कमी हुई है। यहाँ स्पष्ट किया जाना है कि वर्ष 2016–17 में बी०आर०जी०एफ० मद में 5600.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण 5600.00 करोड़ रूपये के विरूद्ध मात्र 1329.40 करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं। इस आलोक में वर्ष 2017–18 में मात्र 2600.00 करोड़ रूपये की प्राप्ति अनुमानित है। इस प्रकार ऊर्जा विभाग का बजट आकार राज्य सरकार ने नहीं बल्कि केन्द्र सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण कम हुआ है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय प्रधान मंत्री के बिहार विशेष पैकेज में भी घोषित राशि उपलब्ध नहीं हुई है। मेरा विपक्ष के माननीय सदस्यों से

यह आग्रह है कि वे केन्द्र सरकार से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बी०आर०जी०एफ० मद की बकाया राशि उपलब्ध कराने का प्रयास करें।

- **पर्यटन विभाग**– वर्ष 2016–17 में 672.49 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2017–18 में 109.87 करोड़ रूपये अर्थात 562.62 करोड़ रूपये की कमी हुई है। वर्ष 2016–17 में केन्द्रीय योजनागत योजना मद में पर्यटन विकास हेतु 613.20 करोड़ रूपये की प्राप्ति के विरूद्ध व्यय प्रस्तावित था। राज्य में पर्यटन विकास के लिए माननीय प्रधान मंत्री के बिहार विशेष पैकेज में उल्लेखित राशि भी राज्य सरकार को प्राप्त न होने के कारण वर्ष 2017–18 के बजट में केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम में राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि वर्ष 2017–18 में, पर्यटन मद में केन्द्र सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं होने के कारण पर्यटन विभाग के बजट आकार में कमी आयी है।

- **अनुसूचित जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग**– वर्ष 2016–17 में 1628.64 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2017–18 में 1301.90 करोड़ रूपये अर्थात् 326.74 करोड़ रूपये की कमी हुई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राज्य की वार्षिक स्कीम में वर्ष 2017–18 में 1525.64 करोड़ रूपये का

उद्व्यय दिया गया है किन्तु विभाग द्वारा 478.50 करोड़ रूपये की राशि निर्माण कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग की मांग में प्रावधानित करायी गयी है जिस कारण अपनी मांग में राशि कम प्रदर्शित हो रही है।

उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण हेतु वार्षिक स्कीम में अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति लोगों के लिए सभी विभागों की मांग में राशि का प्रावधान होता है। वर्ष 2016–17 में 12939.87 करोड़ रूपये के विरूद्ध वर्ष 2017–18 में 16374.68 करोड़ रूपये अनुसूचित जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण हेतु प्रावधानित की गयी है। इस प्रकार 3434.81 करोड़ रूपये का अधिक व्यय इस वर्ष प्रस्तावित है।

- **स्वास्थ्य विभाग**– वर्ष 2016–17 में 8234.70 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2017–18 में 7001.52 करोड़ रूपये अर्थात 1233.18 करोड़ रूपये की कमी हुई है जिसका कारण केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम यथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के केन्द्रांश मद में भारत सरकार द्वारा पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण वर्ष 2017–18 में कम राशि का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2016–17 में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत कुल 3029.

35 करोड़ रूपये के प्राप्ति के विरूद्ध व्यय प्रस्तावित था किन्तु वर्ष 2017–18 में इस मद में मात्र 1600.45 करोड़ रूपये अर्थात 1428.90 करोड़ रूपये की राशि भारत सरकार से कम प्राप्ति अनुमानित है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग के बजट आकार में राज्य की अपने स्कीम की राशि में बढ़ोत्तरी हुई है किन्तु केन्द्र सरकार से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण राशि का प्रावधान कम किया गया है।

- **योजना एवं विकास विभाग–** वर्ष 2016–17 में 3503.89 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2017–18 में 2841.73 करोड़ रूपये अर्थात 662.16 करोड़ रूपये की कमी हुई है, इसका कारण आपात कालीन कोसी बाढ़ पुनर्वास परियोजना में 352.00 करोड़ रूपये का कम प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना में 498.00 करोड़ रूपये का कम प्रावधान किया गया है क्योंकि वर्ष 2016–17 में अधिक राशि का प्रावधान हो गया था जबकि वस्तुतः कम राशि व्यय होनी थी।
- **श्रम संसाधन विभाग–** वर्ष 2016–17 में 781.95 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2017–18 में 468.95 करोड़ रूपये अर्थात 313.00 करोड़ रूपये की कमी हुई है जिसका कारण

औद्योगिक संस्थानों हेतु भू–अर्जन एवं भवनों के निर्माण मद में कम राशि प्रावधानित है। कौशल विकास मिशन के तहत 246.50 करोड़ रूपये का कम प्रावधान किया गया है क्योंकि वर्ष 2016–17 में भू–अर्जन का कार्य एवं निर्माण हेतु राशि पहले ही उपलब्ध करा दी गयी है।

- **पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग–** वर्ष 2016–17 में 1975.54 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2017–18 में 1536.09 करोड़ रूपये अर्थात 439.45 करोड़ रूपये की कमी हुई है जिसका कारण प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति मद में कम राशि का प्रावधान होना है। कम राशि इसलिए प्रावधानित की गयी है कि छात्रवृति में कम राशि का व्यय होना अनुमानित है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन और माननीय सदस्यों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया और व्यावहारिक सुझावों का सरकार कद्र करती है और पूरी ईमानदारी से उनको लागू करेगी। हम विपक्ष में बैठे अपने सहयोगियों से इतनी ही अपेक्षा करते हैं कि हमारी उपलब्धि को नजरअंदाज नहीं करें,–

'' मेरी जिन्दगी यही है कि सबों को फैज पहूँचे,
मैं चिराग–रहगुजर हूँ, मुझे शौक से जलाओ ।''

************जय हिन्द************

आप सभी को याद होगा कि 2015 के केन्द्र सरकार के बजट के पहले एक वेबसाईट में व्यंग छपा था । जिसका शीर्षक था **बजट आलोचना के दस आसान तरीके।** ये तरीके थे

बजट में केवल बातें हैं, कोई ठोस चीज नहीं।

बजट में कोई सुधार जैसी बातें नहीं ।

बजट आम आदमी के लिए नहीं।

बजट में नाम बड़े है, दर्शन छोटे हैं।

यह आदर्शवादी है व्यवाहारिक नहीं।

यह एक सुनहरा प्रयास को अलविदा कहने जैसा है।

भ्रष्टाचार तथा काला धन की बातें गायब है।

यह निराशाजनक है

नयी बोतल में पुरानी शराब है।

- **पूर्व वित्त मंत्री, श्री सुशील मोदी जी** ने कहा कि यह बजट बिल्कुल संक्षिप्त, दिशाहीन, बिना किसी योजना का बजट है जिसमें कृषि, स्वास्थ्य को नजर अंदाज किया गया है। इतना कहने के बाद उनका कहना था कि इस पर प्रतिक्रिया देना बेकार है।

  मैं कहना चाहूंगा कि बजट बनाना तथा पेश करना एक गंभीर Exercise है न कि टी0वी0 शो पर बोलने वाला भाषण जिसमें बी0जे0पी0 के नेता माहिर हैं।

  महागठबंधन की सरकार का यह बजट विकास, गरीबी उन्मूलन तथा वित्तीय स्थायित्व के प्रति प्रतिबद्ध है।

  अतः इससे **गंभीर बात** कुछ हो ही नहीं सकती।

- सामने बैठे माननीय कहते हैं कि **मैं कम बोला।** कहां कम बोला 20 मिनट बोला तथा पूरा बजट इस सदन के समक्ष रखा। माननीय तथा सदन के समय का बचत से इस सूबे का विकास ही होगा। आपको तो हमारा धन्यवाद कहना चाहिए कि हमने पिछले बार की तरह डेढ़ घंटे का समय नहीं लिया।

  हमारा यह मानना है कि बजट का सारांश को बजट Session में संक्षिप्त रूप से पेश करने का परम्परा पूरे देश के सभी विधान मंडल एवं लोक सभा में होना चाहिए।

- अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कुल 102 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी सच्चर कमिटी की शिफारिशों एवं गरीब अल्पसंख्यक जनता के प्रति महागठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

दूसरा Comment यह आया है **कि Growth Rate का बजट में कहीं जिक्र नहीं है।** जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कृषि विकास इस सरकार की प्राथमिकता है और हम अलग से पुनः कृषि रोड मैप बनाने जा रहे हैं।

कुछ लोग यह कर रहें हैं कि **हम केन्द्र सरकार के रहमों करम तथा उनके अनुदान पर निर्भर हैं।** भाई हम तो कह रहें हैं कि अगर ऐसी बात है तो हमारा जो हक बनता है उतना तो हमें दीजिए। यह तो आपको देना ही है। हमारे देश के संविधान द्वारा हमें यह हक मिला है। Co-Operative Federalism इसी को तो कहते हैं। आपने तो 1.25 लाख करोड़ देने का ऐलान किया था। ऐतिहासिक हार के साथ आप वो घोषणा भी भूल गये। विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिया। अल्बत्ता इंदिरा आवास, बी0आर0जी0एफ, Fifteen Points के केन्द्र के अंश को कम कर दिया। हम फिर भी बढ़ रहे हैं, विकास करेंगे तथा विकास का आईना पूरे देश को दिखाएंगे।

हमारा सात निश्चय के सारे Components इस वार्षिक बजट में समाहित है और याद रखा जाए यह महागठबंधन सरकार दूसरा बजट है हम आगे और भी अपने प्रतिबद्धता को आम जनता के सामने रखेंगे। आप धैर्यशील रहकर हमें सूबे के विकास में रचनात्मक सहयोग दें।

बजट पूरे साल आय–व्यय का लेखा जोखा होता है। हम सभी जानते हैं कि केन्द्र सरकार के पास राजस्व वसूली के सभी साधन मौजूद हैं जबकि राज्य सरकार के पास सीमित साधन हैं। आम भाषा में यू कहिए 100 रू0 टैक्स में से केन्द्र सरकार 62 रू0 छीन लेती है और हमें 38 रू0 देकर अपना कर्तव्य का इतिश्री करती है। GST के लागू होने के बाद इस शेयर के हिस्सेदारी को बदलना होगा क्योंकि केन्द्र का पैसा हमारा पैसा है और संघवाद के सिद्धांतों के अनुकूल हमें और हिस्सेदारी देनी होगी तभी हम और मजबूत बजट तैयार करेंगे तथा अपनी जनता के हितों की रक्षा करेंगे।

कुछ महानुभावों का कहना है कि **प्रस्तुत बजट विकास तथा आम आदमी के आय को नहीं बढ़ाएगा।** मैं कहना चाहता हूँ कि विकास के लिए स्त्रोत लोक निवेश से ही आता है। प्रस्तुत बजट में 2017–18 में हम 14 हजार पांच सौ पच्पन करोड़ सरपलस हैं। राज्य सरकार अपने इस सरपलस राजस्व को विकास के विभिन्न Components के लिए खर्च करेगी जिससे आय के संसाधन की भी बढ़ोत्तरी होगी।